

सलाह 'क' अनुभाग में प्राप्त संदर्भ

- 1.1.1. सलाह 'क' अनुभाग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से 5091 संदर्भ कानूनी दस्तावेजों की जांच और विभिन्न मुद्दों पर कानूनी राय/सलाह देने के लिए प्राप्त हुए हैं। इस विभाग के अधिकारियों ने सलाह कार्य के लिए 153 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों में भी भाग लिया।
- 1.1.2. हस्तांतरण विलेखों की दृष्टि से जांच से संबंधित 168 संदर्भ प्राप्त हुए, जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय समझौते भी शामिल हैं।
- 1.1.3. 4608 एसएलपी/मुकदमे संबंधी मुद्दे 89 कैबिनेट नोट/विधायी प्रस्ताव और राज्य विधेयकों और अध्यादेशों से संबंधित 73 संदर्भों की जांच की गई।
- 1.1.4. विधि सलाह देने के अलावा, इस अनुभाग ने माननीय मंत्री और इस विभाग के अधिकारियों को प्राप्त संदर्भों और अन्य संचारों को भी देखा।
- 1.1.5. सलाह अनुभागों से संबंधित 64 आरटीआई आवेदनों और 20 जन शिकायतों का निपटान किया गया।

1. 2. सलाह 'ख' अनुभाग में प्राप्त संदर्भ

- 1.2.1. सलाह ख अनुभाग को विभिन्न मुद्दों पर कानूनी दस्तावेजों की जांच और कानूनी राय/ सलाह के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से 9780 संदर्भ प्राप्त हुए।
- 1.2.2. 148 कैबिनेट नोट/विधायी प्रस्ताव और 2358 एसएलपी/मुकदमे संबंधी मामले जांच/ सलाह के लिए प्राप्त हुए थे।
- 1.2.3. इस विभाग के अधिकारियों ने सलाह कार्य के लिए 132 राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भाग लिया।
- 1.2.4. इस अनुभाग ने माननीय मंत्री के कार्यालय और इस विभाग के अधिकारियों द्वारा प्राप्त संदर्भों और आधिकारिक संचारों को भी देखा।
- 1.2.5. आश्वासनों सहित 76 संसदीय प्रश्नों पर कार्रवाई की गई।

1.3 सलाह 'ग' अनुभाग में प्राप्त संदर्भ

- 1.3.1 जैसा कि सलाह ग अनुभाग में डिजिटलीकरण और पूर्व निर्णयों को समाप्त करने की प्रक्रिया सक्रिय रूप से चल रही है, इस अनुभाग के माध्यम से, विभिन्न विषयों पर केवल सात नए मामले भारत के विद्वान महान्यायवादी, भारत के महासॉलिसिटर और भारत के अपर महासॉलिसिटर की राय के लिए भेजे गए थे जिनमें से पांच मत प्राप्त हुए और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजे गए।
- 1.3.2 अनुभाग ने विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के अधिकारियों को और विभिन्न विषयों पर पूर्व निर्णय खोजने में सामान्य और सचिवीय सहायता प्रदान की है।
- 1.3.3 सलाह 'ग' अनुभाग ने इस वर्ष तीन आरटीआई आवेदनों को निस्तारित किया।
- 1.3.4 944 से 2022 तक के विधि अधिकारियों से संबंधित और 1991 से 2019 तक हमारे विभाग के अधिकारियों की सलाह से संबंधित फाइलों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। 4.59 लाख पन्नों वाली 8937 फाइलों को स्कैन किया गया, जिसमें वर्ष 1944 से 2022 तक महान्यायवादी की राय और वर्ष 1991 से 1997 तक इस विभाग के अधिकारियों की राय से संबंधित फाइलें भी शामिल हैं।
- 1.3.5 सलाह ग में स्कैन की गई 8937 फाइलों में से महान्यायवादी की राय से संबंधित 2061 फाइलें ई-ऑफिस पोर्टल पर अपलोड की गई हैं।
- 1.3.6 वर्ष 1944 से 1997 तक के न्यूनतम 25 वर्ष पुराने रिकॉर्ड के मूल्यांकन के संबंध में फाइलों की विषय सूची तैयार की गई और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की गई।